

## जलवायु परिवर्तन और वन-संरक्षण के लिये डब्ल्यू.आर.आई. और एपको में हुआ एमओयू चर्चा में क्यों?

27 फरवरी, 2023 को जलवायु परिवर्तन पर आयोजित कार्यशाला में पर्यावरण विभाग के एपको और अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान डब्ल्यूआरआई इंडिया के बीच प्रदेश में जलवायु परिवर्तन एवं वनों के संरक्षण संबंधी कार्य पर तकनीकी सहयोग के लिये एमओयू कया गया।

### प्रमुख बडि

- कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नवंबर 2022 में मसिर में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मलेन सीओपी-27 के मुख्य बडिओं पर प्रस्तुतीकरण कर वचिर-वमिरश कया जाना था।
- कार्यपालन संचालक एपको मुजीबुररहमान खान ने कहा कि एमओयू अगले 5 वर्ष में मध्य प्रदेश में जलवायु परिवर्तन एवं वनों के संरक्षण संबंधी कार्य पर केंद्रति होगा। इन वर्षों में उपयोगी एवं सार्थक प्रयास कयि जाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप हम सस्टेनेबल और गरीन डेवलेपमेंट की ओर परस्पर टोस कदम बढाएंगे।
- एपको, राज्य एवं ज़िला स्तर पर डब्ल्यूआरआई इंडिया और संबधति वभिगों को समस्त प्रकार की संस्थागत एवं तकनीकी सहायता देना जारी रखेगा।
- राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र के समन्वयक लोकेंद्र ठक्कर ने कहा कि एपको म.प्र. शासन की वशिषिट संस्था है, जो राज्य शासन को पर्यावरण से संबधति मुद्दों पर परामर्श देने के साथ शोध अध्ययन, योजना कार्य तथा प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास के कार्यों के लिये प्रतबिद्ध है।
- कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सीएन इंटरनेशनल के हेड हरजीत सहि ने जलवायु परिवर्तन से संबधति Loss & Damage वषिय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मध्य प्रदेश जलवायु परिवर्तन के कृषि, जल-संसाधन, पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्रों में एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे परभावों के प्रतति अत्यधिक संवेदनशील राज्य है। उपयुक्त नीतियों के साथ तकनीकी और वत्तितीय संसाधनों की आवश्यकता स्थानीय स्तर के समाधानों को बढाने, लचीला बनाने और हानियों एवं कषतियों को दूर कर मानव क्षमता बढाने के लिये आवश्यक है।
- डब्ल्यूआरआई इंडिया के क्लाइमेट प्रोग्राम की नदिशक उल्का केलकर ने कहा कि भारत में क्लाइमेट एक्शन के मामले में मध्य प्रदेश बहुत महत्त्वपूर्ण राज्य है। यह गरीनहाउस गैस उत्सर्जन के मामले में भारत के शीर्ष 10 राज्य में से एक है।
- राज्य, आर्दर-भूमिकी रक्षा, पारंपरिक जल-संचयन संरचनाओं को पुनर्जीवति करने और देशी मवेशियों की नस्लों को बढावा देने जैसे उपायों को लागू कर रहा है। प्रदेश के बड़े और छोटे शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन का हसिसा बनने समुदायों के लिये भी काफी संभावनाएँ हैं।